2832 करोड़ की अनुपूरक मांगों को मंजूरी दी है दिल्ली विधानसभा ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन। इसके तहत कुल बजट में से 11 उन विभागों को पैसा दिया गया है जिनके लिए वार्षिक बजट में रखी गई राशि कम पड़ गई थी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 3 दिसंबर 2019

शीर्ष अदालत से आम्रपाली के 11 हजार से ज्यादा घर खरीदारों को मिली बड़ी राहत

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनबीसीसी को आम्रपाली की आठ परियोजनाओं का काम पूरा करने का निर्देश दिया है। इनमें ग्यारह हजार से ज्यादा फ्लैट हैं। शीर्ष अदालत ने घर खरीदारों को भी 31 जनवरी तक बकाया राशि का भुगतान किस्तों में या एक मुस्त में करने के निर्देश दिए हैं ताकि आम्रपाली की फंसी परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाई जा सके। कोर्ट अब 13 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा।

शीर्ष अदालत ने एनबीसीसी से जिन परियोजनाओं का काम पूरा करने को कहा है, उनमें आम्रपाली जोडिएक, सफायर फेज 1 और फेज 2, सिलिकॉन सिटी 1 और 2, प्रिंसली एस्टेट, सेंचुरियन पार्क लो राइज और ओ2 वैली शामिल हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की इन परियोजनओं में करीब 11,258 फ्लैट हैं।

जस्टिस अरुण मिश्र और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने 28 बैंकों से भी एक महीने के भीतर घर खरीदारों को लंबित रकम का वितरण करने के लिए कहा है। इन बैंकों ने आवास ऋण देने के लिए सीधे घर खरीदारों या फिर आम्रपाली समूह के जरिए खरीदारों के साथ करार किया था।

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

- एनबीसीसी को आठ प्रोजेक्ट का काम पूरा करने का दिया निर्देश
- घर खरीदारों से भी 31 जनवरी तक बकाए का भुगतान करने को कहा

अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी से पूछा है कि क्या केंद्र द्वारा घोषित 25,000 करोड़ रुपये के कोष से कुछ राशि का उपयोग कर्ज के रूप में अटकी पड़ी आम्रपाली परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है और इसके क्या तौर-तरीके हैं।

पीठ ने कहा कि करीब तीन हजार करोड़ रुपये के बकाए में से घर खरीदारों ने अब तक सिर्फ 105 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। हम घर खरीदारों को 31 जनवरी 2020 तक लंबित राशि का भुगतान किस्तों या फिर एक बार में करने का निर्देश देते हैं।

इससे पहले सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह ने अदालत को बताया कि एजेंसी को पहली नजर में ही मामले में बहुराष्ट्रीय कंपनी जेपी मार्गन द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून 1999 (फेमा) के उल्लंघन के सबूत मिले हैं। इस दौरान कंपनी के भारत में प्रमुख की आम्रपाली समूह के साथ किए गए लेनदेन के बारे में बयान को रिकार्ड भी किया गया।

सुरेखा परिवार को लगाई लताड़ : पीठ ने अदालत में उपस्थित सुरेखा समूह के निदेशक अखिल सुरेखा को भी फटकार लगाई। अदालत ने अखिल सुरखा से घर खरीदारों के 167 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा था, जिसे आम्रपाली समूह से गलत तरीके से निकाला गया था। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसकी तरफ से एक हफ्ते के भीतर कुछ रकम नहीं जमा कराई जाती है तो उसे और दो अन्य निदेशकों नवनीत सुरेखा और विष्णु सुरेखा को जेल भेज दिया जाएगा। उसकी चल और अचल संपत्तियां भी जब्त कर ली जाएगी।

नोएडा के बिल्डर पर 3.28 करोड़ रुपये का जुर्माना

जागरण संवाददाता, नोएडा

सेक्टर-77 स्थित अंतरिक्ष कैनबॉल 3जी बिल्डर पर प्रदूषण विभाग की ओर से 3 करोड़ 28 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यहां नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के नियमों का उल्लंघन होता पाया गया। बिल्डरों पर अवैध रूप से भू-जल दोहन करने और ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में अवैध तरीके से सीवेज का पानी छोड़ने पर यह कार्रवाई एनजीटी से मिले निर्देशों के बाद हुई है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के अधिकारियों वाली समिति ने एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त किए बिना भूजल निकाला जा रहा है। आवेदकों की ओर से दी गई सूचना के अनुसार बिल्डर ने 29 जनवरी, 2011 को परियोजना शुरू की और दिसंबर 2014 से फ्लैटों का कब्जा देना शुरू कर दिया। बिल्डर ने दो बोरवेल स्थापित किए हैं। वर्षा जल संचयन का प्रावधान किया गया है, लेकिन यह चालू नहीं है। इसके अलावा सोसायटी में रहने वाले 475 परिवारों के साथ 560 फ्लैटों के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था नहीं है।

पीठ ने यह भी बताया कि बिजली की आपूर्ति के लिए 500 केवी का डीजल जेनसेट लगाया गया है, लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार इसके लिए चिमनी नहीं लगाई गई है। समिति ने बिल्डर पर 3,28,50,000 रुपये के पर्यावरणीय मुआवजे की सिफारिश की है। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने रिपोर्ट के आधार पर 11 फरवरी को मामले की सुनवाई के लिए अनुपालन रिपोर्ट मांगी।

वकील सालिक शफीक की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2019 तक लगभग 475 परिवार सोसायटी में रहने लगे हैं। बिल्डर नोएडा प्राधिकरण से पानी का कनेक्शन हासिल करने में विफल रहा और केंद्रीय भूजल प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त किए बिना सोसायटी के आंशिक रूप से निर्मित तहखाने में स्थित दो अवैध बोरवेल से पानी की आपूर्ति कर रहा है। याचिका में कहा गया है कि डीजल जनरेटर से निकलने वाला धुआं चिमनी के अभाव में सीधे निवासियों के घरों में प्रवेश करता है। याचिका में आरोप लगाया गया कि निवासियों ने समय-समय पर धरना और विरोध प्रदर्शन किया और नियामक अधिकारियों से भी संपर्क किया, लेकिन अधिकारियों की ओर से बिल्डरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

दिल्ली खेल विश्वविद्यालय पर विस की मुहर

बड़ा कदम ▶ उपराज्यपाल होंगे मुंडका में 70 एकड़ में बनने वाले विश्वविद्यालय के कुलपति, खिलाड़ी ही इसे चलाएंगे

केजरीवाल ने कहा, खिलाड़ियों के लिए साबित होगा मील का पत्थर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा में सोमवार को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय (डीएसयू) विधेयक पारित हो गया। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसे राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा और दिल्ली के उपराज्यपाल इसके कुलपति होंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस विश्वविद्यालय के बनने से चीन से ज्यादा ओलंपिक पदक लाने का भारत का सपना पूरा होगा।

विधानसभा में डीएसयू बिल पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश को आजाद हुए 70 साल हो गए हैं। इन 70 साल में ओलंपिक खेलों में हम सिर्फ 28 मेडल ही ला पाए, जिसमें सिर्फ नौ स्वर्ण हैं। चीन को 2016 के ही ओलंपिक में 70 मेडल मिले। केजरीवाल ने कहा कि इसको पेशेवर खिलाड़ी चलाएंगे। दिल्ली के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन पूरे देश के खिलाड़ी यहां आएंगे प्रशिक्षण लेंगे और देंगे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुंडका क्षेत्र में करीब 70 एकड़ में इसका परिसर बनेगा।

खिलाड़ियों को अलग से पढ़ाई की जरूरत नहीं: अभी तक देश के खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था यह थी कि वह किसी खेल में कुछ भी हासिल कर लें, अकादमिक रूप से उन्हें अलग से पढ़ाई करनी पड़ती थी। अब खिलाड़ियों को किसी और डिग्री की आवश्यकता नहीं है। उन्हें खेलों में प्रदर्शन के आधार पर ही डिग्री मिल जाएगी।

दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता किसी बात पर कुछ यूं मुस्कराते नजर आए। साथ में उपस्थित विधायक भावना गौड़, मंत्री इमरान हुसैन व विधायक सोमनाथ भारती (दाएं)। ध्रुव कुमार

ये युवा भी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा जैसी परीक्षाएं दे पाएंगे। इससे उन्हें काफी राहत मिलेगी।

स्कूल से ले सकेंगे ही दाखिला : इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्कूल भी खुलेंगे, जहां उन बच्चों को दाखिला मिलेगा, जिन्हें खेल में करियर बनाना है। इस स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चों को फिर परीक्षा में पास होने की चिंता नहीं करनी होगी। यह विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी होगी कि बच्चे को अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाया जाए, साथ ही डिग्री भी मिले। इससे शुरू से ही बच्चों में खेल के प्रति उत्साह बढ़ेगा। स्कूल स्तर के शिक्षण के लिए सीबीएसई से संबद्धता होगी।

विश्वस्तरीय संसाधन होंगे : विश्वविद्यालय के पास खेलों में पेशेवर उत्कृष्टता के लिए एक विश्वस्तरीय केंद्र होगा। खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए खेल-विशिष्ट प्रभाग होंगे। ये खेल प्रभाग पूरी तरह से विश्वस्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए सुसज्जित होंगे और खिलाड़ी बनने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए कोचिंग देंगे। प्रत्येक खेल प्रभाग विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में खिलाड़ियों को स्काउट, प्रमोशन और प्रायोजित करेगा। केंद्र में खेल उत्कृष्टता के लिए प्रशिक्षण के अलावा कोच भी तैयार होंगे, साथ ही यहां खेल में रिसर्च करने की सुविधा भी होगी।

दूषित जलापूर्ति के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन से किया वॉक आउट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली में दूषित जलापूर्ति का मुद्दा उठाते हुए सोमवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पहले ही दिन नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता सहित विपक्षी विधायकों ने सदन से वॉक आउट किया। उन्होंने इस विषय पर चर्चा की मांग की थी, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया। सदन से बाहर निकलकर गुप्ता सहित विपक्ष के अन्य सभी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा, ओमप्रकाश शर्मा और जगदीश प्रधान मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही गुप्ता, सिरसा, शर्मा और प्रधान दूषित पानी की बोतलें दिखाते हुए कहने लगे कि शहर में दूषित जल की आपूर्ति की जा रही है। इस पर चर्चा भी होनी चाहिए और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल और विपक्षी सदस्यों के बीच इस बाबत नोकझोंक भी हुई। लेकिन, जब अध्यक्ष ने चर्चा और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने की अनुमति नहीं दी तो उन्होंने वॉक आउट कर दिया।

सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में गुप्ता ने कहा, दिल्ली की दो करोड़ जनता को हो रही दूषित जलापूर्ति पर हम चर्चा कराना चाहते थे। चर्चा के लिए हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और कार्यस्थगन का प्रस्ताव भी दिया। लेकिन, स्वीकार नहीं किया गया। दु:ख की बात है कि सरकार इस ज्वलंत समस्या पर चर्चा से बच रही है। उन्होंने बताया कि विपक्ष ने सदन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने कहा कि विपक्ष गंदे पानी की सप्लाई के विरूद्ध अपनी आवाज उठाना जारी रखेगा।

केजरीवाल बोले–भाजपा के लोगों को तीर्थयात्रा पर भेजूंगा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : इस बार अनधिकृत कॉलोनियों की रजिस्ट्री दिलवाकर रहेंगे। आप (भाजपा) नहीं देंगे तो केजरीवाल देगा। यह कहना है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। सोमवार को दिल्ली विधानसभा में अनधिकृत कॉलोनियों पर पेश हुए संकल्प पत्र पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों से कांग्रेस–भाजपा अनधिकृत कॉलोनियों पर राजनीति करती रही है। लेकिन, हमने यह खेल ही खत्म कर दिया। भाजपा के लोगों को तीर्थयात्रा पर भेजेंगे। अब अगला चुनाव इन कॉलोनियों के विकास पर लड़ा जाएगा। लोगों को इन कॉलोनियों पर कानून नहीं रजिस्ट्री चाहिए। जब तक रजिस्ट्री न हो जाए किसी को भरोसा नहीं। मुझे जानकारी मिली है कि कुछ लोगों को रामलीला मैदान में रजिस्ट्री देकर प्रचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक चुनाव से पहले वादा ही किया जाता रहा है। अब जनता को हाथ में रजिस्ट्री चाहिए।

आठ हजार करोड़ से चमका दीं अनधिकृत कॉलोनियां : मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों को चमकाने के लिए 8 हजार करोड़ से भी अधिक का बजट लगाया। यहां पानी, नाली, सड़क, सीवर की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए तेजी से काम करवाया। इन कॉलोनियों में गरीब, मध्यम वर्ग, प्रवासी पूर्वांचल समाज के लोग रहते हैं। उन्होंने एक कहानी सुनाते हुए कहा कि जिस तरह से एक डॉक्टर स्वस्थ्य मरीज को भी दवाई देकर पैसे कमा रहा था उसी तरह भाजपा–कांग्रेस भी अनधिकृत कॉलोनियों के विकास की जगह राजनीतिक रोटियां सेंक रही थी।

पुणे से दिल्ली तक 'यात्री' ने उड़ाया इंडिगो का विमान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

आइजीआइ एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने के चलते पुणे से दिल्ली आ रहे इंडिगो एयरलाइंस के विमान को उड़ाने की जिम्मेदारी उसमें बैठे एक 'यात्री' को सौंपी गई। चूंकि कोहरे के बीच विमान की लैंडिंग कराने के लिए पायलट का कैट-3बी प्रशिक्षित होना जरूरी है, लेकिन विमान का पायलट इस विशेष तकनीक से प्रशिक्षित नहीं था। ऐसे में उसमें यात्री के रूप में सवार कैप्टन पुणे से दिल्ली तक विमान को उड़ा कर लाए।

एयरपोर्ट अधिकारी के मुताबिक, शनिवार की सुबह 7.30 बजे इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान संख्या 6ई-6571 को पुणे से दिल्ली के लिए उड़ान भरनी थी। इसी दौरान पुणे एयरपोर्ट पर विमान के उड़ान से पूर्व प्रबंधन को आइजीआइ एयरपोर्ट पर सीजन का पहला कोहरा फैलने की सूचना मिली। कोहरे के कारण एयरपोर्ट पर दृश्यता काफी कम थी। इस स्थिति में नियम के मुताबिक, कैट-3बी से प्रशिक्षित पायलट ही विमान को रनवे पर उतार सकता है। लेकिन उक्त उड़ान के पायलट इससे प्रशिक्षित नहीं थे। लिहाजा इसी विमान से ड्यूटी समाप्त कर वापस लौट रहे इंडिगो एयरलाइंस के ही कैट-3बी से प्रशिक्षित कैप्टन को विमान उड़ाने की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद विमान को सुबह करीब 9.10 बजे आइजीआइ एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया।

एयरलाइंस प्रवक्ता के मुताबिक, उड़ान में देरी के कारण यात्रियों की परेशानी होती। इसके मद्देनजर एयरलाइंस ने ऐसा निर्णय लिया था। इस उड़ान के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी की गई थीं। यात्री के रूप में विमान में बैठे पायलट को सीधे कॉकपिट में प्रवेश नहीं दिया गया था। पहले ब्रीथ एनेलाइजर समेत उनके सभी अनिवार्य जांच किए गए, जिससे विमान उड़ाने से पहले नियमित पायलट को गुजरना पड़ता है। विमान के कैप्टन के बदलने के लिए सभी तरह की आंतरिक मंजूरियां ली गई थीं और उनका नाम रोस्टर में भी शामिल कराया गया था।

क्रू मेंबर की कमी से गो एयर की 10 उड़ानें लेट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : क्रू मेंबर की कमी के कारण आइजीआइ एयरपोर्ट से अलग-अलग स्थानों के लिए उड़ान भरने वाली गो एयर की करीब 10 उड़ानें सोमवार को देरी से उड़ीं। उड़ानों का संचालन आधा घंटे से लेकर करीब पांच घंटे की देरी से हुआ। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। देश के विभिन्न एयरपोर्ट पर खराब मौसम, रनवे की मरम्मत व अन्य कारण से मौजूद क्रू मेंबर की उड़ान कर्तव्य समय सीमा (एफडीटीएल) 18 से 24 घंटे पूरी हो चुकी थी। लिहाजा क्रू मेंबर की कमी के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई।

एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, आइजीआइ पर उड़ानें रविवार आधी रात बाद से सुबह करीब 10 बजे तक प्रभावित रहीं। यात्रियों का आरोप है कि उनकी उड़ानें पुनर्निर्धारित किए जाने के बावजूद इसकी सूचना उन्हें समय पर नहीं दी गई थी। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद इस बारे में पता चला। जिसके बाद उन्हें घंटों एयरपोर्ट पर गुजारने पड़े। कई लोग महत्वपूर्ण काम से जा रहे थे। लेट होने के कारण उनका काम खराब हो गया।

आरोप है कि यात्रियों ने जब इसकी शिकायत एयरलाइंस कर्मियों से की तो उन्हें उड़ान के समय का संतोषजनक जबाव नहीं दिया गया। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि देरी की सूचना यात्रियों को मोबाइल और ईमेल पर दे दी गई थी।

हुक्का पीने पर क्लास में बैठने से रोकने के मामले में स्कूल को नोटिस

जासं, नई दिल्ली : हुक्का पीने की वजह से छात्र को क्लास में बैठने से रोकने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के अलकनंदा स्थित कालका पब्लिक स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया कि मामले की अगली सुनवाई तक बच्चे को क्लास में बैठने दिया जाए। याचिका पर अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। हुक्का पीने पर क्लास में बैठने से रोकने के खिलाफ छात्र प्रथम कुमार ने अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के माध्यम से याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता छात्र ने मांग की है कि वह पढ़ना चाहता है और स्कूल आने की अनुमति दी जाए। याचिका के अनुसार नर्सरी क्लास से ही स्कूल में पढ़ने वाले नौवीं क्लास के छात्र प्रथम कुमार का एक वीडियो स्कूल प्रिंसिपल तक पहुंचा। जिसमें वह हुक्का पीते हुए नजर आ रहा था। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने उसे क्लास में बैठने से रोक दिया। छात्र की तरफ से पेश अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने दलील दी कि छात्र ने न तो स्कूल परिसर के अंदर ऐसा किया और न ही वह स्कूल ड्रेस में था।

पीएमआइसी ने लगाई ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी के चयन पर मुहर

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

उत्तर प्रदेश की परियोजना निगरानी एवं क्रियान्वयन समिति (पीएमआइसी) ने जेवर एयरपोर्ट के निर्माण एवं संचालन के लिए चयनित ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी के नाम पर मुहर लगा दी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सोमवार को लखनऊ में पीएमआइसी की बैठक हुई। अब प्रदेश कैबिनेट में इसे मंजूरी के लिए रखा जाएगा। जेवर एयरपोर्ट के लिए प्रति यात्री राजस्व की सबसे अधिक बोली लगने पर पीएमआइसी ने नियाल के अधिकारियों प्रशंसा की।

बता दें कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 29 नवंबर को खोली गई फाइनेंशियल बिड ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी ने अडानी इंटरप्राइजेज को पछाड़ते हुए हासिल की है। कंपनी ने प्रति यात्री 400.97 रुपये राजस्व की बोली लगाई थी।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (नियाल) के अधिकारियों द्वारा पीएमआइसी के सदस्यों को सोमवार को हुई बैठक में जेवर एयरपोर्ट के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी के चयन की जानकारी दी गई। इस दौरान पीएमआइसी के सदस्यों ने नियाल के अधिकारियों से जानकारी ली कि जेवर एयरपोर्ट के लिए प्रति यात्री मिलने वाला राजस्व अन्य एयरपोर्ट के सापेक्ष कितना अधिक या कम है। इस पर नियाल अधिकारियों ने समिति को जानकारी दी कि देश के सभी एयरपोर्ट से प्रति यात्री मिलने वाले राजस्व के सापेक्ष जेवर एयरपोर्ट से मिलने वाला राजस्व सबसे अधिक होगा। समिति ने इसके लिए नियाल के अधिकारियों की प्रशंसा की और परियोजना को समय से पूरा कराने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। पीएमआइसी की मुहर लगाने के बाद जेवर एयरपोर्ट के निर्माण एवं संचालन के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी के चयन का प्रस्ताव प्रदेश कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट की मुहर लगाने के बाद कंपनी के चयन की अधिसूचना जारी होगी।

नियाल के नोडल अफसर शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि पीएमआइसी ने ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी के चयन पर सहमति दे दी है। इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सबसे अधिक राजस्व की बोली लगने पर पीएमआइसी ने प्रशंसा की है।

इस सर्दी का सबसे ठंडा दिन रहा सोमवार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : नवंबर भले ही अपेक्षाकृत गर्म रहा हो, लेकिन दिसंबर की शुरुआत में ठंड का आलम यह रहा कि दिसंबर की शुरुआत के दो दिन लगातार तापमान में कमी आई और सोमवार इस सर्दी का सबसे ठंडा दिन रहा। न्यूनतम तापमान महज 8 डिग्री सेल्सियस पर सिमट गया। लोदी रोड पर तो न्यूनतम तापमान और भी कम महज 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस सप्ताह सर्दी का प्रकोप और बढ़ेगा।

सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी तरह न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम 8 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर 46 से 97 फीसद रहा। हालांकि सोमवार को कोहरे का असर कुछ कम हुआ। इससे सोमवार को दृश्यता में भी सुधार हुआ। मंगलवार की सुबह भी कोहरे की संभावना कम है, लेकिन न्यूनतम तापमान महज 7 डिग्री रह सकता है। हवा की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार से शनिवार तक कोहरा देखने को मिल सकता है। इस दौरान अधिकतम 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी।

केंद्र व दिल्ली सरकार की नूरा कुश्ती से बढ़े प्याज के दाम : सुभाष चोपड़ा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कहा कि प्याज का दाम केंद्र और दिल्ली सरकार की नूरा कुश्ती से बढ़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी गोदामों में 32 हजार टन प्याज सड़ रहा है और जनता प्याज के लिए तरस रही है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनकी भी जमाखोरों के साथ मिलीभगत है। सोमवार को चोपड़ा के नेतृत्व में पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर प्रदर्शन किया। प्याज की माला पहनकर प्रदर्शन कर रहे चोपड़ा व मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा सहित अन्य प्रदर्शनकारी महिलाओं को पुलिस ने उस वक्त हिरासत में ले लिया, जब उन्होंने सड़क के बीच में बैठकर चक्का जाम कर दिया।

प्रदेश महिला कांग्रेस द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन में शामिल महिलाएं जमाखोरों पर कसो लगाम, सस्ते करो प्याज के दाम, केजरीवाल शर्म करो, प्याज के दाम कम करो आदि नारे लगाती हुईं मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रही थीं। इस दौरान महिलाओं और पुलिस के बीच कई बार झड़प भी हुई। चोपड़ा व शर्मा ने दोनों सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि गरीब आदमी आज सब्जी खाना तो दूर की बात, सूखी रोटी और चटनी के लिए भी तरस रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 72 घंटे में प्याज के दाम कम नहीं हुए तो प्रदेश कांग्रेस केजरीवाल और पासवान दोनों का ही घेराव करेगी।

32 हजार टन प्याज सड़ने के मामले में संजय सिंह ने केंद्र से मांगी जानकारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : प्याज के बढ़ते दाम पर सियासत खत्म नहीं हो रही है। सोमवार को आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान को पत्र लिखकर 32 हजार टन प्याज सड़ने से संबंधित प्रमाण मांगे। सिंह ने पासवान को लिखे पत्र में पूछा है कि क्या 32 हजार टन प्याज एक ही दिन में सड़ गया? अगर प्याज सड़ने की जानकारी मिली तो समय रहते उसे सस्ते दामों पर जनता और राज्य सरकारों को क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया? क्या 32 हजार टन प्याज सड़ने का कोई प्रमाण आपके पास है? यदि है तो उसकी वीडियो और भंडारण संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

अब सेटेलाइट से की जाएगी हाईवे पर अतिक्रमण की निगरानी

डीपी आर्य, सोनीपत : हरियाणा में हाईवे पर स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण की निगरानी अब पराली प्रबंधन की तरह की जाएगी। राज्य परिवहन प्राधिकरण और हाईवे अथॉरटी ने हरसैक (हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर) के साथ इसकी तैयारी कर ली है। सेटेलाइट से प्राप्त चित्रों के आधार पर संबंधित पर शिकंजा कसा जाएगा। इसके साथ ही हाईवे पर खराब होने वाले वाहनों को हर हाल में 30 मिनट के अंदर हटवाना होगा। इसका पत्र परिवहन सचिव ने जिले के सभी थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों को भेज दिया है।

सेटेलाइट की निगरानी से पराली जलाने वालों को रोकने में बड़ी मदद मिली है। इसी तर्ज पर अब हाईवे पर अतिक्रमण करने वालों पर रोक लगाने की तैयारी है। इससे स्थायी रूप से अतिक्रमण करने वालों के साथ ही होटल और ढाबा संचालकों की निगरानी भी की जाएगी। हाईवे किनारे ढाबों के सामने मनमाने तरीके से वाहन पार्क कर दिए जाते हैं। इनके कारण हादसे भी हो चुके हैं। परिवहन विभाग की ओर से होटल और ढाबा संचालकों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अब इनके सामने सड़क पर पट्टी भी लगाई जाएगी।

रास्ता साफ

नरेला और गाजीपुर में डीडीए का इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉरिडोर लगभग तैयार हो गया है। केमिकल और कागज व्यापारियों को यहां प्लॉट भी आवंटित कर दिए गए हैं

बाहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित होगा थोक कारोबार

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

लंबी कवायद के बाद पुरानी दिल्ली का थोक कारोबार दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। नरेला और गाजीपुर में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) का इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉरिडोर (आइएफसी) लगभग तैयार हो गया है। केमिकल और कागज व्यापारियों को यहां प्लॉट भी आवंटित कर दिए गए हैं, जहां निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ अन्य कारोबारों को भी प्लॉट देने के लिए कागजी प्रक्रिया चल रही है। संभावना है कि 2020 में पुरानी दिल्ली के काफी कारोबार यहां से स्थानांतरित हो जाएंगे। नतीजा, यहां पर न केवल भीड़भाड़ कम होगी बल्कि इस क्षेत्र के घुटते जीवन को भी नया आयाम मिलेगा।

चांदनी चौक व खारी बावली सहित पुरानी दिल्ली से थोक मार्केट के लगभग एक दर्जन थोक कारोबार नरेला और गाजीपुर में बने आइएफसी में जल्द स्थानांतरित होंगे। इसका उद्देश्य पुरानी दिल्ली से भीड़ कम करना है। आइएफसी में थोक सामान को सड़क और रेलमार्ग से अन्य राज्यों तक एवं अन्य राज्यों से यहां तक लाना-ले जाना सहज हो जाएगा। साथ ही शहर के भीतर वाहनों और व्यापारियों व खरीदारों की भीड़ पर भी लगाम लगेगी।

पुरानी दिल्ली से भीड़ भाड़ कम करने के लिए नरेला और गाजीपुर में आइएफसी बनाने की योजना वर्ष 1980 में शुरू की गई थी। लेकिन, बाद में विभिन्न कारणों से यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई। कोर्ट के आदेश पर योजना आगे बढ़ी तो डीडीए ने भी प्लॉट आवंटन के काम में तेजी दिखाई। योजना के मुताबिक यहां पर पार्क, फायर स्टेशन, लोकल शॉपिंग कांप्लेक्स सहित अन्य सभी सुविधाएं भी होंगी। हालांकि यहां कारोबार शिफ्ट करने की अंतिम समय सीमा कोर्ट ने दिसंबर 2018 तय की थी, लेकिन निर्माण कार्य में विलंब होने के कारण अब स्थानांतरण का काम 2020 तक ही हो पाएगा।

नरेला में दो महीने में स्थानांतरण शुरू होने के आसार : नरेला स्थित आइएफसी में 50-50 वर्ग मीटर के लगभग 12 सौ प्लॉट काटे गए हैं। 29 हेक्टेयर में केमिकल मार्केट तैयार की गई है। केमिकल के लगभग 650 थोक व्यापारियों को प्लॉट भी आवंटित कर दिए गए हैं, जिनमें से करीब 500 पर निर्माण कार्य शुरू चल रहा है। निर्माण पूरा होने के बाद दो महीने में शिफ्टिंग शुरू होने की बात कही जा रही है। यहां पर 19 हेक्टेयर में ट्रांसपोर्टरों को भी प्लॉट दिए जा रहे हैं।

> चांदनी चौक सहित पुरानी दिल्ली में भीड़ कम करने एवं उसे उसका शाहजनाबाद का पुराना स्वरूप लौटाने की कोशिश चल रही है। इस दिशा में प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इन प्रयासों का असर भी जल्द ही दिखाई देगा।
>
> –तरुण कपूर, उपाध्यक्ष, डीडीए

गाजीपुर में प्लांट आवंटन का कार्य जल्द होगा शुरू : आइएफसी गाजीपुर में पेपर ट्रेडिंग के लिए जगह दी जा रही है। इसके अलावा यहां पर किराना, ड्राइ फूट, इलेक्ट्रिकल, मसाला, स्पेयर पार्ट्स सहित कई अन्य कारोबार करने वालों के आवेदन आने भी शुरू हो गए हैं। इन कारोबारियों को भी प्लॉट आवंटन करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी।

अब नए साल में खुलेगा एम्स का ओपीडी ब्लॉक

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रदूषण की मार लोगों की सेहत पर तो भारी पड़ ही रही है, इससे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की परियोजना भी प्रभावित हुई है। प्रदूषण के कारण निर्माण कार्